दो तीन महीनों के लिए प्रति मास 1.5 लाख मी० टन गेहूं का आवंटन करने के लिए सितम्बर, 89 में अनुरोध प्राप्त हुआ था । इसके मुकाबले इस राज्य को सितम्बर से जनवरी, 1990 के महीनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

माह	आवंटन ('000 मी०टन में)
सितम्बर, 89	100.0
अक्तूबर,89	125.0
नवम्बर, 89	150.00
दिसम्बर, 89	100.0
जनवरी, 90	100.0

खाद्य तेल : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन के समय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मांग, खुले बाजार में देशी तेलों की उपलब्धता और मूल्यों, सरकार के पास तेल के भंडारों और संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है । इस आवंटन का उद्देश्य उचित मूल्यों पर देशी खाद्य तेलों की कमी को पूरा करना है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना नहीं है ।

इस समय महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेल में से 6,500 मी० टन का आवंटन किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए समस्त आवंटन का एक बड़ा हिस्सा है ।

महाराष्ट्र में खुली बिक्री की चीनी (फ्री सेल शूगर) के कोटे में वृद्धि

111. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है कि मई, 1989 में खुली बिक्री की चीनी (फ्री सेल शूगर) की कीमतों में वृद्धि हुई है जिसके कारण खुली बिक्री की चीनी की सप्लाई में कमी आ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सरकार से निवेदन किया है कि पर्याप्त मात्रा में खुली बिक्री की चीनी की पूर्ति महाराष्ट्र सरकार को समय रहते की जाए जिससे कि खुले बाजार में बढ़ती हुई कीमतें रोकने में मदद मिले ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन देश में चीनी के किसी भी लाइसेंसशुदा थोक व्यापारी को बिक्री करने के लिए फैक्ट्रियों से मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की जाती है । मास के दौरान पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और मौसम के लिए समूची स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मई, 1989 के महीने के लिए मासिक मुक्त बिक्री का 5 लाख मीटरी टन स्वदेशी चीनी का कोटा निर्मुक्त किया गया था जबकि नई, 1988 में 4.50 लाख मीटरी टन का कोटा निर्मुक्त किया गया था ।

तथापि, मई, 1989 में महाराष्ट्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए 500 मीटरी टन मुक्त बिक्री की आयातित चीनी निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया था । उस समय विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मामूली बचे स्टाक तक ही आयातित चीनी के आवंटन को सीमित रख गया था । अतः भारतीय खाद्य निगम के पास महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध 23 मीटरी टन आयातित चीनी की थोड़ी मात्रा नियंत्रित माध्यमों से बिक्री करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मुहैया की गई थी ।

Manufacture of Electronic Goods in the Country

112. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what were the total value of electronic goods manufactured in the country from January 1, 1987 till November 30, 1989;

(b) what were the corresponding figures of value of these goods during the years 1984-85 and 1985-86; and

(c) the names of foreign countries which have been allowed participation in Indian ventures for production of electronic goods alongwith the broad terms of their collaboration agreements?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) The value of electronic goods manufactured in the country during the period January 1, 1987 till November 30, 1989 is about *Rs. 18,320* crores.

(b)

year	value (Rs. crore)
1984-85	2081
1985-86	2880

(c) During the last three years, foreign collaborations have been approved with USA, UK, Federal Republic of Germany, Japan, Italy, France, Switzerland, Australia, Netherlands, Canada, Singapore, South Korea, Tiawan etc. These collaborations are broadly in the nature of Technical know-how, financial participation, Design and Drawing and Training of personnel etc. All the foreign collaborations approved in the Electronics sector are within the normal policy framework applicable to all sectors of Industry. Foreign equity holdings upto 40 per cent only has been allowed in all areas of electronics except in the case of 100 per cent. Export Oriented Units and units in the Export Processinig Zones.

Meetings of Courts and Executive Councils of Central Universities

118. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the number of meetings of the Court, Executive Council and Academiic Council of Central Universities held during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): The information is being collected and shall be laid on the Table of the House.

Foreign Visits of Chairman of UGC and VCS of Central Universities

114. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 12 given in the Rajya Sabha on the 2nd November, 1988 and state:

(a) what was the number of visits paid to foreign countries by the Chairman of the University Grants Commission during the last three years and by the Vice Chancellors of Central Universities after 2nd November, 1988 till date alongwith the purpose of these visits and the names of the countries visited;

(b) the total amount of money spent on these visits; and

(c) the period spent on the visits by the Chairman of University Grants Commission and Vice Chancellors of Central Universities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) to (c) The information is being collected and shall be laid on the Table of the House.

Publication of Urdu Encyclopaedia

115. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the first volume of Urdu Encyclopaedia has not been published so far;

(b) what are the reasons for the delay in the publication of the first and subsequent volumes of the said Encyclopaedia;

(c) what action Government propose to take to expedite publication of the Encyclopaedia; and

(d) by when the first volume would be published?